Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 1 - 2018

प्रेस की राजनीतिक भूमिका का आलोचनात्मक विशलेषण (मण्डल कमीशन आन्दोलन में)

डॉ0 परमेश्वर कुमार पाण्डेय

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओ के समक्ष समाज के दबे कुचले और पिछडे वर्ग के लोगो का उत्थान एक प्रमुख समस्या रही। परम्परागत भारतीय समाज ने एक वर्ग ऐसा था जो शिक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुदढता की स्थिति को प्राप्त था। समाज का एक बडा वर्ग दलित, शोषित, सम्मान और शिक्षा की दृष्टि से पिछडा हुआ था। भारतीय संविधान में यह धोषणा की गयी कि भारत के सभी नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख उददेश्य है। संविधान की मूल भावना यह भी थी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वंतत्रता के साथ साथ अवसर की समानता की स्थापना करना राज्य का मूल दायित्व होगा। इसलिए मौलिक अधिकार के अन्तर्गत कानून के समक्ष सबकी समानता का भाव स्पष्ट किया गया। धर्म, रंग, जाति, लिग और जन्म के नाम पर विषमता को समाप्त करने की शपथ ली गयी। जन्म रोजगार में अवसर की समानता एंव छुआ–छूत की समाप्ति का उददेश्य भी मौलिक अधिकार के अन्तर्गत किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण एंव लोक कल्याण की भावना के विकास पर पर बल दिया गया। राज्य के नीति निर्माण में निर्देशक तत्वो की सूची प्रस्तुत की गयी। लोगो के लिए समान नागरिक आचार संहिता, अनुसूचित जन–जातियें के लिए शैक्षणिक एंव आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु योजना और समाज के अन्य कमजोर तबको के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाए लागू करने के निर्देश राज्य को प्राप्त हुए।

संविधान के आधार पर 1953–1955 के मध्य प्रथम पिछडा वर्ग आयोग का गठन किया गया। संविधान की धारा 340 के तत्वावधान में आयोग बना जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। 1955 में इसकी में इसकी संस्तुतियां मेमुरेण्डम आफ एक्शन के रूप में रखा गया। इसमें 2399 जातियों को पिछडे वर्ग के रूप में माना गया। ससंद में इस पर किसी प्रकार की बहस नही हुई। यह माना गया कि पिछडे वर्गो के उत्थान के लिए जाति की जगह आर्थिक स्थिति को आधार माना जाना चहिए। वस्तुत: केन्द्रीय सरकार की उहापोहवादी नीति के कारण काका कालेलकर रिपोर्ट ठण्डे विस्तर में डाल दी गयी। उस समय प्रेस की नजर में इसकी कमियो पर दृष्टि डाली गयी।

1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। जनता पार्टी की इस सरकार ने पिछडे वर्गो के उत्थान को ध्यान मे रखते हुए 20 दिसम्बर 1978 को बी0पी0 मण्डल की अध्यक्षता में दूसरे पिछडे वर्ग आयोग की धोषणा की। 31 दिसम्बर 1980 को आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी।

*प्राचार्य, जी0डी0एस0बी0 पी0जी0 कालेज, डेरापुर, कानपुर देहात।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

इस आयोग में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्ग को केन्द्रीय नौकरियो में आरक्षण दिलाने के लिए मापदण्ड निश्चित करने का कार्य सौपा गया। 1990 तक यह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पडी हुई थी। गैर काग्रेसी विपक्षीर दल ने इसको लागू करने के लिए अनेक बार जनता से वायदे किये, लेकिन 10 वर्ष तक इस रिपोर्ट पर कार्यान्वयन नही किया जा सका।

7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिह के नेतत्व में कार्यरत गैर काग्रेसी जनता दल की सरकार ने एकाएक मण्डल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने की धोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि देश जातिगत संधर्ष में उलझता चला गया। आम सहमति के अभाव मे रिपोर्ट को लागू करने का प्रभाव इतना गम्भीर पडा कि समाज की समरसता टूटती हुई दिखायी देने लगी। यह सत्य था कि देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिह के नेतत्व में कार्यरत गैर काग्रेसी जनता दल की सरकार ने एकाएक मण्डल कमीशन की सस्तुतियो को लागू करने की धोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि देश जातिगत संधर्ष मे उलझता चला गया।

आम सहमति के अभाव मे रिपोर्ट को लागू करने का प्रभाव इतना गम्भीर पडा कि समाज की समरसता टूटती हुई दिखायी देने लगी। देश में ऐसा विभत्स जातीय संधर्ष का संकट कभी पैदा नही हुआ था। प्रश्न यह था कि पिछडो के अभ्युत्थान के नाम पर अवसरो का बटवारा क्या जाति के नाम पर होगा या आर्थिक पिछडेपन के नाम पर। राष्ट्र की योग्य क्षमताओ का कही उपयोग तो रूक नही जायेगा,देश जातीय टुकडो में बंट तो नही जायेगा। यह प्रश्न राष्ट्र की राजनीति के वातावरण में तैर रहे थे। मण्डल विरोधी आन्दोलन हिसा की उचाई नापने लगा। शासन और पुलिस की पर्यरताएं बढी योग्यताएं अग्नि को समर्पित होने लगी। वोट बैंक के लालच में प्रत्येक राजनीतिक दल सवेदना शून्यता के शिकार थे। राष्ट्र के इस जातीय संधर्ष के संकट में राजनीतिक दलो ने नकारात्मक भूमिका निभाई और वे लगभग निष्क्रिय से दिखाई पडे। राष्ट्र में नियंत्रण शून्यता का अभाव अपने चरम पर दिखाई पड रहा था। जातिगत विखराव को रोकने मे प्रशासनिक मशीनरी असफल हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन न्यायपलिका, राष्ट्रीय नेतृत्व किंकर्त्तव्यविमूढ से खडे थ। ऐसा लगा कि भारतीय समाज उदारता और सहिष्णुता की अपनी परम्परा भूल चुका है।

उददेश्य

अध्ययन क्षेत्र में मण्डल कमीशन आन्दोलन मे प्रेस की स्थिति याद करना–

साहित्य समीक्षा शोध पत्र से सम्बन्धित साहित्य जो उपलब्ध हुआ वर्तमान समय मे आरक्षण का आधार जातीय नही बल्कि अर्थिक आधार पर करने की मांग जोरो पर है। सरकार तथा भिन्न भिन्न दल भी इस दिशा में सोचने पर मजबूर है विषय के लिए सामग्री का चयन दुरूह कार्य है। शोध पत्र के सन्दर्भ में हमने ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक प्दाति का सहारा लिया है। प्रस्तुत शोध पत्र को गभीर दृष्टिकोण के आधार प्रस्तुत करना हमारा उददेश्य है। मण्डल कमीशन के लागू होने के बाद भी देश में असन्तोष व्याप्त है।

जातिगत आरक्षण के लागू होने के बाद भी केवल जाति के अन्तर्गत सक्षम लोग ही इसका लाभ उठा रहे है जिनको आरक्षण के बाद भी अपनी जातिगत प्रतिस्पर्दा में बहुत पीछे है। अतः आरक्षण जातिगत नही आर्थिक आधार पर होना चहिए। शोध पत्र से सम्बन्धित साहित्यो का अभाव है। इसमें दो तीन पुस्तके एंव पत्र, पत्रिका एंव समाचार पत्रो में जो सामग्री उपलब्ध हुई है उनका उल्लेख मैने सन्दर्भ गन्थ सूची में किया है।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

शोध प्रविधि

शोध पत्र के सन्दर्भ में हमने ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लिया है। प्रस्तुत शोधपत्र में महत्वपूर्ण पत्रकारो एंव उनके विचारो को समाहित किया गया है। राजनीतिक दलो, चाहे वह सता पक्ष का हो या विपक्ष का हो वोट की राजनीति में लिपट हुआ प्रस्तुत किया गया है। मण्डल कमीशन के विरोध में बोलने पर पिछडो के वोट कटने का भय तथा मंडल कमीशन के समर्थन में बोलने पर सामान्य जातियो के वोट कटने का भय व्याप्त है। इसलिए राजनीतिक दलो के नेता मौन है। किसी से साक्षात्कार की स्थिति में वे खामोश एंव टाल मटोल करते है।

विमर्श

मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रेस ने उसक व्यापक संवैधनिक और राजनैतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के विश्लेषण में निष्पक्षता और पूर्वग्रहता दोनो के भाव दिखाई पड़ते है। मण्डल कमीशन रिपोर्ट का व्यापक राजनैतिक संवैधानिक विश्लेषण सबसे पहले अरूण शौरी ने किया। शौरो ने रिपोर्ट को एक महान भूला बताया इसमें महाविनाश के छिपे हुए बीज देखा। उन्होने रिपोर्ट को जातिवाद की सडाध घोषित किया। शौरी के अुनसार मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राष्ट्र निर्जीव हो जायेगा, प्रतिभा रूक जायेगी। सत्ता प्राप्त करने और वोट के लिए जातिवादी राजनीति करना राष्ट्र के लिए घातक है।

यह केवल मंडल की कृपा और बी0पी0 सिंह की अधिकृत घोषणा से नही हुआ कि आधी सरकारी नौकारिया जाति के आधार पर दी जायेगी, जो उनको सभालने के लिए सक्षम तथा योग्य नही है। भीडवादी प्रचार का आलम यह है कि अन्य पिछडे वर्गो के लिए तय किये गये 27 प्रतिशत के आरक्षण के साथ मण्डल ने यह वाक्य भी चस्पा कर दिया "खुली स्पर्धा मे मेरिट के आधार पर चुने गये" अन्य पिछडी जातियो के उम्मीदवारो को 27 प्रतिशत आरक्षण में एडजस्ट नही किया जायेगा, दूसरे शब्दो मे जो मेरिट की कसौटी पर खरे नही उतरते उन्ही को कोटा भरने के लिए नौकरियां दी जायेगी। स्वाभाविक है कि यह बात अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवारो पर भी लागू होगी जिनके लिए पहले से ही सभी नौकरियो में 22.5 प्रतिशत का आरक्षण पहले से तय है यह कोटा न सिफ नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए तय है। बल्कि हर स्तर पर पदोन्नतियो पर भी लागू होगा।

निष्कर्ष

भारत की स्वाधीनता के बाद समाज में अमीर एंव गरीब के बीच गहरी खाई थी। यधपि कि समाज की समरसता में कोई कमी नही थी संविधान निर्माण के समय से ही समाज में दबे कुचले लोगो का उत्थान प्रमुख समस्या रही है। कांग्रेस जो प्रारम्भ से ही सत्ता के शीर्ष पर थी ब्राहम्ण हरिजन और मुस्लिम वोट बैक के आधार पर सत्ता सूत्र संभाला। लेकिन इसमें हरिजनो के प्रति उनका दृष्टिकोण ढुलमुल वाला ही रहा। परिणाम यह हुआ कि लम्बे समय में भी अनु–सूचित जाति और जनजाति का वह उत्थान देखने को नही मिला, जिसकी उम्मीद प्रारम्भ में की गयी थी। इन जातियो को सरकारी सेवाओ मे आरक्षण की सुविधा भी दी गयी। वस्तुतः अनुसूचित जाति, जनजातियो में भी आरक्षण का लाभ उन्ही को मिला जो इस वर्ग में मक्खनी सतह थे। 1984 के बाद दलित अपने आत्म सम्मान की लडाई में रत हो गये, उन्हे कांशीराम जैसा नेता मिला। दलितो के इस नेतृत्व मे समाज को सवर्ण बनाम दलित में विभाजित कर दिया। कांग्रेस ने सतर्कता का परिचय देते हुए 1956 में काका कालेलकर आयोग जिसे प्रथम पिछडा

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है का गठन किया। रिपोर्ट की संस्तुतियो को 1977 तक लागू नही किया गया। 1977 में जब पहली बार देश में गैर काग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो लोहिया के सिद्धान्तो के आधार पर अपने वोट बैक को सुदृढ करने हेतु कारगर कदम उठाया। जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग को एकजुट कर लिया जाय तो कांग्रेस फिर सत्ता में वापस नही आ पायेगी। इसी कार्य योजना के तहत मेरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछडा वर्ग आयोग मन्डल आयोग की नियुक्ति की। 31 दिसम्बर 1980 को इसकी संस्तुतियां सरकार को दे दी गयी। अगस्त 1990 तक इन संस्तुतियो पर कोई कियावन्वयन नही किया गया। मण्डल आयोग के नाम पर स्वर्ण और पिछडा गठबन्धन कांग्रेस से तोड दिया गया। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार सता में आई। प्रारम्भ में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की संस्तुतियो को लागू करने में ढिलाई की। लेकिन जनता दल में पिछडो का नेतृत्व देवी–लाल ने सभाल लिया परिणाम यह हुआ कि नेतृत्व के प्रश्न पर जनता दल में भी खीचतान शुरू हुई।

7 अगस्त को देवीलाल बनाम विश्वनाथ प्रताप सिंह के संघर्ष में मण्डल आयोग की संस्तुतियो को आनन–फानन में लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कर दिया। परिणाम यह हुआ कि समाजिक द्वन्द की गति तेज हो गयी। आम सहमति के अभाव में रिपोर्ट को लागू करने का परिणाम इतना गम्भीर पडा कि समाज का ताना–बाना टूटता हुआ दिखाई पडने लगा। पूरा समाज अगडे बनाम–पिछडे में विभक्त हो गया।

आन्दोलन अंहिसात्मक नही हिंसात्मक था। देश अराजकता के शिखर पर था। पुलिस प्रशासन न्यायपालिका, राष्ट्रीय नेतृत्व, कि कर्तव्य विमूढ से खडे थे। छात्रो के लिए यह तनाव पूर्ण स्थिति थी। दिल्ली में राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का सिलसिला शुरू किया। सैकडो नौजवानो ने मंण्डल के विरोध मे।देश के विभिन्न भागो में आत्मदाह की राजनीति को शुरू किया। आत्मदाह के इस जंगल में केन्द्रीय सरकार बौनी और संवेदना शून्य लग रही थी। समाज की दृष्टि में सरकार और राजनीतिक दल घृणास्पद हो गये थे।

इस खतरनाक स्थिति में प्रेस ने अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। समाज का बडा वर्ग मण्डल की संस्तुतियो को नही जानता था। उसके दूरगामी परिणाम के बारे में वह अनभिग्य था। प्रेस ने बन्द हुए बहस को प्रारम्भ किया। यह सर्वमान्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायापलिका के बाद प्रेस सरकार का चौथा खम्भा है। उसकी निष्पक्षता से समाज पर गम्भीर प्रभाव पडता है। मण्डल समर्थक नेताओ ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय प्रेस सवर्णो के हाथ की कठपुतली है। नेताओ का यह भी आरोप था कि मण्डल विरोधी दंगो को उकसाने में प्रेस का हाथ है। लेकिन इस तरह के दृष्टिकोण पूर्वाग्रत से ग्रसित है। यदि सभी की असफलता के बाद प्रेस ने यथार्थ को समाज में उजागर करने का सार्थक प्रयास न किया होता तो शायद देश जातिगत संघर्ष के मुहाने पर खडा होता और उसे टूटते देर लगती। प्रेस ने लोगो के सोच में परिवर्तन करने का काम किया। प्रेस ने स्पष्ट रूप से सभी राजनीतिक दलो को स्वार्थवादिता के कटघरे में खडा कर दिया मण्डल आयोग पर कानूनी संवैधनिक, सामाजिक, आर्थिक आरक्षण की सफलता–असफलता पर बहस किया। यह भारतीय लोकतन्त्र की गहराई ही कही जायेगी। कि जब देश अन्धरे के गर्त में जा रहा था तो प्रेस ने उसे रोशनी दिखाई। युवाओ को उग्र आदोलन और आत्मदाहो के जंगल से निकालने का रास्ता बनाया वस्तुतः मण्डल विरोधी आन्दोलन के दौरान समाज

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

और राष्ट्र का नेतृत्व प्रेस ही कर रहा था। अरूण शौरी, राजेन्द्र अवस्थी, गिरिलाल जैन, मधु लिये, सुरेन्द्र मोहन, राजेन्द्र यादव, अरूण पुरी, चन्दन मित्रा, राजकिशोर, जैसे वरिष्ठ पत्रकारो ने अपनी लेखनी उठाई उन्होने मण्डल आयोग के सन्दर्भ में जो बहस की वह अभूतपूर्व है। उन्होने वकीलो, संविधान विदों समाज के बौद्धिक वर्ग को प्रेरित किया तथा बैद्धिक वर्ग में आग की लपटो पर पानी डालने का कार्य किया। प्रेस ने ऐसी भूमिका आपातकाल और प्रेस बिल के खिलाफ किया था। वस्तुतः प्रेरा सुधारवादी एक स्तम्भ है।

निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि मण्डल आन्दोलन के दौरान प्रेस की सार्थक भूमिका इसलिए महत्वापूर्ण है कि प्रेस के प्रभाव से आरक्षण का मूल भूत प्रश्न विवाद ग्रस्त नही बन पाया और सामाजिक न्याय की पवित्र अवधारणा जातिगत न्याय का रूप नही ले सकी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. Agarwal 1975 Castes Community and Tribes in India, Contemporary Social Science 4(8) April -June P-5-6.
[2]. Anon, 1966, Bibliography on Seheduled Caste.
[3]. Business India (Periodical) J-16
[4]. India Planning Commission, 1990 Annual Report 1989-90 Planning Commission, New Delhi, 100p.
[5]. India Ministry of Information and Broad Casting 1988-89 Reference New Delhi - 129D.
[6]. India Today (Periodical), 1990 Sept 15.
[7]. Hindustan Times (Newspaper) 1990 The Mandul Mass Hindustan Times Sept 19 Editorial.
[8]. Hoshier Singhand Malik Jagdish Kumar 1984 The Mandal Commission Report a Plea for Shave in Power, Political Science Review 23(3-4) July-September, P 250 -268.
[9]. Meenakshi, 1990, The Plight of Brahmins India Express, September 18.
[10]. Khushwant Singh, 1990 Mandal Mess, Hindustan Times, September 8.
[11]. Kothari Rajni, 1990, Meaning of Mandal Hindustan Times.
[12]. Madhok Balraj, 1990 Creating New Tensions Hindustan Times.
[13]. Roy, Burman B.K., 1990 Burman Questions.
[14]. India Government 1968, National Policy on Education Ministry of Education New Delh 28 P.
[15]. Roy T.S, 1972, Free Education for All Social Welfare 19(9) December, P-18-20.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**